R.N.I. No. RAJHIN/2020/79075

कागज़ की कश्ती

पाक्षिक समाचार पत्र

मो. 9829250181
ई-मेल : shiv.ksg@gmail.com
सम्पादक : शिवकुमार शर्मा

वर्ष - 6 | अंक - 20 | किशनगढ़, बुधवार, 22 अप्रैल 2026 | कुल पृष्ठ - 4 | (पाक्षिक) | मूल्य रु. 360/- (वार्षिक)

बिहार में भाजपा के सम्राट चौधरी बने मुख्यमंत्री

पटना। भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। चौधरी बिहार के ऐसे 24वें व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर मिला है। सम्राट ने शपथ लेने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पैर छुकर आशीर्वाद लिया। पटना के लोकभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सुबह 10.56 बजे चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य के रूप में गठबंधन की सहयोगी जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। इन दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। चौधरी की अनुशंसा पर राज्यपाल ने विभागों का बंटवारा किया है। मुख्यमंत्री चौधरी के पास 29 विभाग हैं। वहीं जदयू के हिस्से में 18 विभाग आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में सम्राट चौधरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि चौधरी अपने अनुभव और जन सेवा के प्रति समर्पण के साथ प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सफल होंगे।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। कुमार ने सम्राट की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और कहा कि उनकी देखरेख में राज्य की प्रगति निरंतर जारी रहेगी।

नागरिकों को वोट के लिए मजबूर नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अनिवार्य मतदान लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनावों में भागीदारी को दमनकारी या बाध्यकारी उपायों से लागू नहीं कर सकते।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों से मताधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया था कि अदालत चुनाव आयोग को अनिवार्य मतदान के लिए दिशानिर्देश बनाने और बिना वैध कारण वोट न देने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मताधिकार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते।

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाए। करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद सबसे पहले संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के जरिए 850 सीटें करने का प्रावधान था। इसके पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया। इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल. परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया।

इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिला आरक्षण के लागू करने के तरीके का नहीं बल्कि महिला आरक्षण के पूरे प्रस्ताव का ही विरोध किया है। इंडी गठबंधन के सदस्यों ने चर्चा में यह तो कहा कि महिला आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन उन्होंने इसको लागू करने के बारे में 'अगर मगर किंतु परंतु' लगाया और उनका यह तरीका लागू करने के तरीके पर नहीं बल्कि महिला आरक्षण का ही विरोध है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन यहां इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में इसके नियम निहित हैं और परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करना और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि संविधान में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के शासन काल में इन सीटों की संख्या को एक जगह रोक दिया गया। गृहमंत्री ने कहा कि आज देशभर में 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। उन्होंने विपक्ष से इन विधेयकों का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक मत एक मूल्य का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से लागू होगा।

समाचार पत्र की खबरों का स्रोत

समाचार पत्र के संवाददाता, PRO Ajmer, DIPR Jaipur, PIB Jaipur, दूरदर्शन भारत के माध्यम से तथा अन्य स्रोतों से समाचार पत्र की खबरों का प्रकाशन किया जाता है।

सम्पादक

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खुले

उत्तरकाशी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार को देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन दर्शनों के लिए खुल गए। इस तरह उत्तराखंड की मशहूर चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी हो गया। दोनों धामों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश-प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की है।

SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI GIRLS' COLLEGE, KISHANGARH
(PG College Affiliated to M.D.S. University, Ajmer)

B.A. | B.Com. (Pass Course & Hons.)
B.Sc. (Bio., Mathematics & Home Science)
BBA | BCA (AICTE Approved)
B.Sc.B.Ed. | B.A.B.Ed.*
(4-Year Integrated Programmes)
*Admission through PTET only
M.A. (Geography, Home Science & Hindi)
M.Sc. (Mathematics & Zoology)
M.Sc. (Computer Science)

All Govt. Scholarships Available
Attractive Rebate Policy up to 75% for Meritorious Students

NSS | NCC | Scouts & Guides (Rangers) | UBA | RKCL Courses
Sports Academy | Competitive Exam Preparation Classes
Counselling Sessions Available | Hostel Facilities Available Nearby

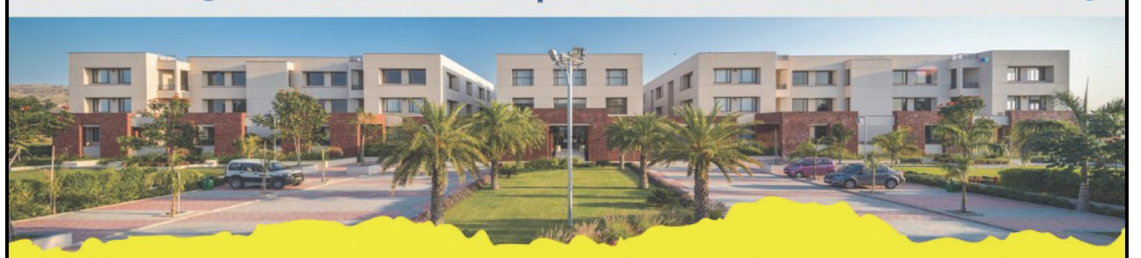

Ajmer Road, Madanganj-Kishangarh, 305801, District - Ajmer (Rajasthan)
Tel.: +91 1463 257000, WhatsApp @ +91 70730-77222
E-mail: info@rkgirlscollege.edu.in, Web: www.rkgirlscollege.edu.in

पुष्कर माहेश्वरी सेवा सदन में कृष्ण भवन का लोकार्पण समारोह बदला अखाड़े में, जमकर चले लात-घूंसे

शिवकुमार शर्मा

पुष्कर। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के प्रबंधकारिणी के चुनाव को लेकर विवाद बुधवार को उस वक्त हिंसक हो गया, जब नवनिर्मित कृष्ण भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते हंगामे के बीच जमकर लात-घूंसे चलने लगे। इससे सेवा सदन परिसर और आसपास का पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि एक गुट के लोगों को सेवा सदन से बाहर सड़क तक करीब 100-100 मीटर तक दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। देश में प्रबुद्ध समझे जाने वाले समाज को शर्मसार करने वाली घटना से उपजे अफरा-तफरी के माहौल से क्षेत्र में तनाव बना रहा। पुलिस और समाज के प्रबुद्धजनों के हस्तक्षेप के बाद बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए।

सेवा सदन के नवनिर्मित कृष्ण भवन का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत गोविंददेव गिरी महाराज ने जैसे ही लोकार्पण किया। इसी दौरान सेवा सदन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर बिड़ला, श्याम सुंदर बिड़ला, सुभाष काबरा सहित दूसरे गुट के लोग ज्ञापन देने व महाराज का स्वागत करने के नाम पर कार्यक्रम में पहुंचे और नारेबाजी व हंगामा करना शुरू कर दिया। दोनों गुटों की ओर से नारेबाजी होने लगी। एक ओर रामकुमार भूतड़ा गुट के समर्थक गोविंद देव गिरी महाराज के जयकारों से माहौल गूंजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर विरोधी गुट अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध जता रहे थे। टकरावपूर्ण माहौल से कुछ क्षणों के लिए स्वयं महाराज भी असहज नजर आए। तनाव के बीच महाराजश्री ने कृष्ण भवन का फीता खोला, शिलालेख से पर्दा हटाया और आवश्यक फोटो सेशन कराया। इसके तुरंत बाद सदन अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें कार्यक्रम स्थल से रवाना करवाया। जैसे ही महाराज कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए, दोनों गुटों के बीच कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। गाली-गलौच के बीच दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले व मारपीट हुई। इस दौरान कुछ समाजबंधुओं को परिसर से बाहर सड़क तक दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। समा के बुजुर्ग लोगों को नीं छोड़ा गया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिनमें एक व्यक्ति की आंख पर गंभीर चोट आई, वहीं कई लोगों के कपड़े फट गए। वहीं 75 वर्षीय सेवा सदन के मंत्री मुरलीधर झंवर ने आरोप लगाया कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि गिरने के बाद भी उन्हें लातों से पीटा गया। घटना के बाद विरोधी गुट ने खंडेलवाल धर्मशाला में बैठक कर रणनीति बनाई और एकजुट होकर पुलिस थाने पहुंचा। पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर बिड़ला ने कमल चांडक (जोधपुर), विजय शंकर मूंदड़ा, सूरज नारायण लाखोटिया (अजमेर), तेज करण सोनी, ललित सोनी, अभिषेक सोनी, अर्पित काबरा, अक्षय तापड़िया, श्रीगोपाल सोनी, दीपक सोनी सहित 10-15 अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अवैधानिक रूप से भवन का लोकार्पण किया गया।

भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता : भजनलाल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली पांच बैरकों के निर्माण, पुलिस कार्मिकों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर एवं उत्सव फंड में पांच करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान और पुलिस कामिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसफ व विपिन पाण्डेय, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एसआई सीताराम, गिरधारी लाल व एएसआई गोविंदराम को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से लाए गए नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर एक पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। नकल माफिया पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ ही प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा 23 नए पुलिस थाने सृजित किए हैं।

रिया ने इंटरनेशनल शूटिंग बॉल में जीता गोल्ड

मदनगंज-किशनगढ़। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रिया जोरम ने नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने संस्थान, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। नेपाल शूटिंग बॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग बॉल सीरीज में रिया ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। कड़े मुकाबले में रिया के सटीक खेल कौशल और रणनीतिक प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। पूरे इंडिया-नेपाल टूनामेंट के दौरान रिया का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसकी बदौलत उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। रिया की इस ऐतिहासिक जीत पर कॉलेज के निदेशक एवं सचिव सुभाष अग्रवाल ने कहा कि यह जीत रिया के समर्पण और कड़े अभ्यास का प्रतिफल है। प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र पाटनी ने कहा कि कॉलेज में शिक्षा के साथ-साथ खेलों के लिए जो माहौल दिया जा रहा है, यह उपलब्धि उसी का सुखद परिणाम है। बी. ए. तृतीय सेमेस्टर की छात्रा रिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, कोच और कॉलेज के सहयोगी वातावरण को दिया है।

बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन जलाया अराजकता का पुतला

मदनगंज किशनगढ़। बजरंग दल द्वारा राष्ट्रविरोधी ताकतो के विरोध में राष्ट्रविरोधी अभियान के तहत किशनगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हिन्दूवादी संगठनो के पदाधिकारियों ने बताया कि नासिक के टीसीएस में उजागर हुआ है कि अनेक नगर में लव जिहाद, वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, रेल भूमि, सेना की भूमि पर अवैध कब्जा, खान पान की वस्तुओं को अपवित्र करना सहित अनेक मुद्दों को लेकर विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हिन्दूवादी संगठनो के पदाधिकारी रविन्द्र रंगमंच से शांति मार्च निकालते हुए मुख्य चौराहा पहुंचे और अराजकता का पूतला जला विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महेश सैन, प्रदीप बधवा, राजू खटाना, महेन्द्र सिंह, सूर्य प्रकाश शर्मा, सहित अनेक जन मौजूद रहे।

अन्य राज्यों के आरक्षित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

शिवकुमार शर्मा

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया, कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की ओर से दायर याचिका को खारिज करते कहा, राज्यवार आरक्षण व्यवस्था संविधान और कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। फेडरेशन की ओर से याचिका में बताय गया, कि अन्य राज्यों के एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटा की आरक्षित सीटों पर भाग लेने और कम किए गए क्वालिफाइंग परसेंटाइल का लाभ दिया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था, कि केंद्र सरकार की ओर से सीटें खाली रहने के कारण क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया गया है, ऐसे में सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान राज्यवार होती है। ऐसे में एक राज्य में आरक्षित वर्ग में आने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में उसी श्रेणी का लाभ नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया, कि राजस्थान सरकार की काउंसलिंग गाइडलाइन पहले से ही यह प्रावधान करती है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (जनरल) श्रेणी में ही माना जाएगा। यह नियम पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान लगातार लागू रहा है, इसलिए इसे बीच में बदला हुआ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा, यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमिसाइल आधारित आरक्षण नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है, बशर्ते वे उस श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करें। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी माना कि मेडिकल की पोस्टग्रेजुएट सीटों का खाली रहना उचित नहीं है, लेकिन केवल सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता।

आरके पाटनी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने वूमन यूथ पार्लियामेंट में लिया भाग

मदनगंज-किशनगढ़। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कॉलेज, किशनगढ़ की छात्राओं ने माय भारत बजट क्वेस्ट के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय स्तर के पीएम संवाद कार्यक्रम में सहभागिता महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। छात्रा सिद्धि सोनी, नंदिनी खंडेलवाल एवं हंसिका चौधरी ने वूमन यूथ पार्लियामेंट में भाग लेकर अपने विचारों से सशक्त नेतृत्व एवं जागरूक नागरिकता का परिचय दिया। वहीं 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संवाद का अवसर प्राप्त किया, जो उनके लिए एक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। महाविद्यालय के निदेशक एवं सचिव सी.ए. सुभाष अग्रवाल ने कहा कि हमारी छात्राओं की यह उपलब्धि उनके परिश्रम और संस्थान के शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। यह अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी। प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्र पाटनी, विषय विशेषज्ञ डॉ. राधा गुप्ता, डॉ. रूचि मिश्रा ने हर्ष जताया।

शिक्षा विभाग ने नए सत्र में चार पुस्तकों को किया विलोपित

जयपुर। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में चार पुस्तकों को विलोपित करने के आदेश दिए हैं। समाज शिक्षा राजस्थान के उपनिदेशक ने जारी आदेश में बताया कि कक्षा नौ-'राजस्थान का स्वतंत्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा' हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम, दो-कक्षा 'दसवीं का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति' हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम, तीन-कक्षा 11 का 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' भाग-एक हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम, चार कक्षा 12-'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' भाग-दो हिन्दी-अंग्रेजी माध्यम को स्कूलों में नहीं पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में मिलता है पाठ्यक्रम निःशुल्क- सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम निःशुल्क मिलता हैं, लेकिन निजी स्कूलों में विद्यार्थी बाजार से खरीदकर लाते हैं, जिन अभिभावकों ने पाठ्यक्रम खरीद लिया है, उनके सामने अब पुनः नई पुस्तकें खरीदनी पड़ेगीं।

स्वामी व प्रकाशक शिवकुमार शर्मा के लिए मुद्रक गजेन्द्र के. बोहरा द्वारा नितिन प्रिन्टर्स, बंगाली गली, कचहरी रोड, अजमेर (राज.) से मुद्रित एवं कार्यालय नन्द निकुंज, जैन स्थानक गली, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) से प्रकाशित। सम्पादक : शिवकुमार शर्मा मो. 9829250181, ई-मेल : shiv.ksg@gmail.com

अपनी सामर्थ्य से अधिक रुचिकर बनने का प्रयास करना सबसे बड़ी गलती है।
- वाल्टर बगेट

सम्पादकीय

बुधवार, 22 अप्रैल 2026

महिला कोटे से जुड़े संविधान बिल के लुढ़कने के सियासी हित

इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकजुटता ने पुनः सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से जुड़ा था, 16 अप्रैल 2026 को वोटिंग में गिर गया। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) की आवश्यकता थी, जो सरकार के रणनीतिकारों ने नहीं जुटा पाए। शायद पहली बार सदन में अमित शाह की रणनीति पिट गई। इसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि मोदी सरकार के लिए 12 साल में पहली बड़ी संवैधानिक

हार हुई है, जो विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे "संविधान पर हमला" बताकर कांग्रेस-विपक्ष की रणनीति की जीत घोषित की, जबकि भाजपा इसे विपक्ष विरोधी हथियार बनाने की योजना बना रही है। एक सत्ता विरोधी रणनीति के तहत जहां विपक्ष ने बिल को "छलावा" करार दिया, वहीं दावा किया कि यह परिसीमन और चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। वहीं, एक एनडीए नेता के अनुसार, बिल गिरने से सरकार अब सड़क पर विपक्ष को महिलाओं के अधिकारों के नाम पर घेरेगी। हालांकि, सरकार ने शेष दो बिल (परिसीमन और अन्य) आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि वे मुख्य बिल पर निर्भर थे। एचएम अमित शाह और पीएम मोदी विपक्ष के विरोध को कांग्रेस के इतिहास से जोड़कर जनता में प्रचार करेंगे। यह 2029 चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज कर सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का पुनः संदेश गया है। वहीं, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने के लिए रणनीतिक बदलाव कर सकती है, खासकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हार के बाद। समझा जाता है कि सरकार नई विधेयक रणनीति के तहत दो या तीन नए विधेयक ला सकती हैः पहला लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेगा, जिसमें एससी/एसटी के लिए सब-कोटा भी शामिल होगा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं? दूसरा परिसीमन आयोग स्थापित करेगा, लेकिन इसे राज्यों के अनुमोदन से अलग रखा जा सकता है ताकि दो-तिहाई बहुमत आसान हो। सरकार का मानना है कि विपक्ष से सहमति निर्माण के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी सभी दलों को पत्र लिखकर सर्वसम्मति की अपील कर चुके हैं, इसी सिलसिले में कांग्रेस और अन्य विपक्षियों से बातचीत जारी है। महिला कोटा बिल को 2029 चुनावों से पहले लागू करने के लिए 2011 जनगणना पर आधारित संशोधन पर जोर दिया, और नई जनगणना-परीक्षण का इंतजार खत्म किया जाएगा। इसके निमित्त संसदीय प्रक्रिया यह हैं कि विशेष सत्र बुलाकर संशोधित बिल पेश करना संभव होगा, जहां 18 घंटे लोकसभा और 10 घंटे राज्यसभा चर्चा होगी। वहीं सड़क पर प्रचार के साथ विपक्ष को ओबीसी हितों पर घेराव, जिससे राजनीतिक दबाव बनेगा। यह 2029 से पहले बहुमत जुटाने की कोशिश होगी। इस प्रकार देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को 2029 से पहले लागू करना संवैधानिक रूप से जटिल है, क्योंकि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया अनिवार्य है जो 2011 जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। इसका संभावित विकल्प संशोधित बिल पुनर्प्रस्तावहै जिसके तहत सरकार दोबारा संशोधित विधेयक ला सकती है, जिसमें लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला कोटा सुनिश्चित हो, लेकिन विपक्ष सहमति के बिना दो-तिहाई बहुमत मुश्किल है। इसलिए विपक्ष से सर्वसम्मति की पहल तेज है। सरकार सभी दलों से बातचीत तेज कर विशेष सत्र बुलाना, परिसीमन को अलग रखकर बिल पास करवाना, हालांकि विपक्ष इसे "परिसीमन साजिश" मान रहा है। जहाँ तक व्यावहारिक बाधाओं की बात है तो परिसीमन आयोग को पब्लिक हियरिंग और प्रक्रिया में कम से कम 2-3 वर्ष लगते हैं, इसलिए 2029 चुनाव से पहले पूरा होना असंभव है। वहीं बिल गिरने से अब अगली जनगणना (2031) और उसके बाद के परिसीमन तक (2034+) देरी तय, दक्षिणी राज्यों की चिंताएं टल सकती हैं। सरकार सड़क प्रचार पर जोर देगी। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर मुख्य रूप से परिसीमन प्रक्रिया, ओबीसी/एससी/एसटी सब-कोटा और राजनीतिक साजिश को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैंः- पहला, परिसीमन साजिशः बिल को लोकसभा/विधानसभा सीटें बढ़ाने और 2011 जनगणना पर परिसीमन से जोड़ा गया, जिसे विपक्ष ने उत्तर भारत (विशेषकर भाजपा शासित राज्यों) को लाभ पहुंचाने वाली "सीट रिबनिंग" करार दिया। फलतः दक्षिणी राज्य अपनी सीटें खोने के डर से विरोधी हो गए। दूसरा, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुपस्थितिः 33% महिला कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब-कोटा न होने से सामाजिक न्याय का उल्लंघन ठहराया, और इसे "सवर्ण महिलाओं के लिए" नया मौका बताया। तीसरा, संविधान पर हमलाः राहुल गांधी ने इसे "संविधान बचाओ" का मुद्दा बनाया, और दावा किया कि बिल चुनावी नक्शा बदलकर विपक्ष कमजोर करेगा। इस प्रकार राजनीतिक तर्क देते हुए विपक्ष ने इसे "छलावा" कहा, क्योंकि लागू होने में 2029-34 तक देरी होगी। इसलिए एकजुट होकर वोटिंग में भाजपा नीत एनडीए को हराया। वहीं, मोदी सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया, जो 25-30 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। परिसीमन पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि परिसीमन 2011 जनगणना पर आधारित होगा, जो निष्पक्ष है और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा; यह सीट वृद्धि के साथ संतुलित होगा। अमित शाह ने चुनौती दी कि यदि विपक्ष संशोधन चाहे तो सदन एक घंटा रोकें, वे तुरंत बदलाव लाएंगे।

परशुराम जन्मोत्सव पर युवा प्रतिभाओं का सम्मान

पुष्कर। अखिल राजस्थान परशुवंशीय आदि गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत दो दिवसीय कार्यक्रमों की शुरूआत शनिवार को हुई। महासभा के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश मिश्र ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित परशुराम मंदिर में कार्यक्रम के तहत शनिवार सुबह आगंतुक समाजबंधुओं का पंजीयन किया तथा जागरण में गायककारों ने भजनों की सरिता बहाई।

समाज के भवन में युवा शक्ति सम्मेलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष प्रेमप्रकाश मिश्र ने बताया कि इस बार सम्मेलन में नवाचार किए गए। जिसमें मंच पर समाज की युवा शक्ति को स्थान दिए गए। मंच संचालन भी युवाओं द्वारा किए गए। अध्यक्ष के रूप में सुश्री अनुराधा गेपाला, सचिव के रूप में रुपेश मिश्र, सह सचिव के रूप में विशाल कुलीचवाल एवं उपाध्यक्ष के रूप में सुश्री कविता शर्मा को मंचस्थ होने

हेतु सर्वसम्मति से चुना गया। युवा शक्ति सम्मेलन के दौरान युवा मन की बात और सामाजिक सरोकार विषय पर रामानंद शर्मा, रोहिणीकांत खैरीवाल, आनन्द शर्मा, खुशबू स्वामी, कविता शर्मा इत्यादि युवाओं ने समाज के चहुंमुखी विकास, मुख्यधारा से जुड़े रहने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर अपने विचार रखे। मंच संचालन सुश्री पूजा ने किया । युवा शक्ति सम्मेलन के अंतर्गत हुई प्रतियोगिताओं के बीस विजेताओं और संभागियों को मोमेंटो, प्रमाण पत्र, नकद राशि, भगवान परशुराम जी फ्रेमड फोटो एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मिश्र ने समाज में व्याप्त घोड़ी-गीत जैसी फिजूलखर्ची वाली प्रथाओं को बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ओढावनी प्रथा के दौरान दी जाने वाली सीख को बंद करने की आवश्यकता है। वहीं रिंग सेरेमनी एवं दशोटन इत्यादि आयोजन सादगी से ही किए जाने की अपील की। उन्होंने प्री वेडिंग सिस्टम पर एतराज जताते हुए दिखावे और अनावश्यक व्यय से बचने का आह्वान किया। सचिव राजनारायण तिवारी ने युवाओं को सफलता के मंत्र दिए और महासभा की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रामस्वरूप कौशिक एवं नरोत्तम पाठक ने ने भी संबोधित करते हुए युवाओं को प्रेरणा पाथेय प्रदान किया।

किशनगढ़ वन रेंज ने वन विभाग को एक वर्ष में दिया एक करोड़ से अधिक का राजस्व

किशनगढ़। किशनगढ़ वन रेंज ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित करते हुए एक बार फिर अजमेर वन मंडल में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपना परचम लहराया है। यह वन रेंज पिछले पांच वर्षों में भी इतना राजस्व अर्जित नहीं कर पाया, जितना इस वर्ष 31 मार्च 2026 तक हुआ है। वन अधिकारियों के अनुसार किशनगढ़ वन रेंज वित्तीय वर्ष 2024-25 से पूर्व पांच सालों में कुल 57 लाख रुपए का ही राजस्व अर्जित कर पाया था। लेकिन इस बार सीधा दुगुना राजस्व वन विभाग को दिया है। अधिकारी इसकी मुख्य वजह विभाग द्वारा मिले चार पहिया वाहन, जुमार्ने के नए प्रावधान को बताते हैं। वन कर्मचारी हाईवे सहित आसपास के जंगलों में बोलेरो से गश्त करते हुए यह कार्य कर पा रहे हैं और अवैध लकड़ी, कोयला व वन अधिनियम से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल वाहनों पर जुमार्ने से राजस्व मिल रहा है। हालांकि किशनगढ़ वन रेंज को विभाग की ओर से सालाना 13 लाख रूपए का ही लक्ष्य मिला था। लेकिन एक साथ करोड़ों का राजस्व यहां के इतिहास में पहली बार मिला है।

मंडी में शुरु हुआ कारोबार-चना व रायड़ा की हुई बंपर आवक

मदनगंज किशनगढ़। जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में पलदारों की तीन दिन की हड़ताल के बाद मंडी में कारोबार शुरु हुआ। दस हजार से अधिक बोरा चना व छह हजार से अधिक बोरा सरसो यानी रायड़ा सहित अन्य जींस की आवक हुई। करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ जबकि मंडी प्रशासन को भी 18 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। मालूम हो कि पीक सीजन में पलदारों की हड़ताल से मंडी में तीन दिन कारोबार प्रभावित रहा। किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान दूसरी ओर मंडी की ओर रुख करने लगे थे। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान ने पलदारों व व्यापारियों को सदबुद्धि दी और हड़ताल सम्मानजनक समझौता व दोनो की आपसी सूझबूझ के साथ समाप्त हो गई। मंडी प्रशासन तो नियम कानून के दायरों की बात कर स्वयं को किनारा सा कर लिया था।

मदनगंज व्यापार मंडल के पूर्व मंत्री हरिकिशन छापरवाल ने बताया कि मंडी में अच्छा व्यापार हुआ। करीब दस हजार बोरे चना, छह हजार बोरे रायड़ा, पांच सौ बोरे मूंग सहित अन्य जींस की आवक रही। मंडी में चना 5025 से 51 सौ रुपए, रायड़ा 6300 से 6700 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहे। मंडी में जींस की अच्छी आवक हो रही है। किसान व व्यापारी दोनो के चेहरे खिले नजर आए। जहां तीन दिन पूर्व तक अशांति का माहौल था। अब सुनसान मंडी एक बार फिर गुलजार होने लगी है।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में विज्ञान पत्रकारिता विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित

मदनगंज किशनगढ़। बांदरसिंदरी स्थित राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारिता विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। पीआरओ अनुराधा मित्तल ने बताया कि इस दौरान कर्नाट की पत्रकार डा अनुभा जैन ने कहा कि एक अच्छा विज्ञान पत्रकार केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझाता है कि उसका समाज के लिए क्या महत्व है। डॉ. अनुभा जैन ने विज्ञान पत्रकारिता और समाचार लेखन की विभिन्न शैलियों पर व्याख्यान देते हुए उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया। यह व्याख्यानमाल सीयूआर के संस्कृति एवं मीडिया अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित की गई। इसका विषय प्रयोगशाला से सुर्खियों तक रखा गया। इसके तहत व्याख्यात्मक लेख, समाचार और फीचर लेखन की संरचना विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों एवं शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुलपति प्रो. आनंद भालेराव के संरक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और मीडिया जगत के बीच संवाद को सशक्त करना तथा छात्रों को पेशेवर करियर के लिए तैयार करना है। संस्कृति एवं मीडिया अध्ययन विभाग के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. प्रांता प्रतीक पटनायक ने बताया कि इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराया गया, ताकि वे तकनीक, अंतरिक्ष और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संचार की वास्तविक आवश्यकताओं को समझ सकें। इसदौरान सामाजिक विज्ञान स्कूल के अधिष्ठाता प्रो अमिताभ श्रीवास्तव, आयोजन समिति के सदस्य डॉ. अनूप कुमार, डॉ. निकोलस लकड़ा, एवं डॉ. नीरू प्रसाद सहित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन विभाग की छात्रा विदुषी एवं कृति कुंदु द्वारा संयुक्त रुप से किया गया।

प्रशासन की मनमानी के खिलाफ विधायक उतरे सड़क पर

मदनगंज किशनगढ़। किशनगढ़ के मुख्य बाजार से गुरुवार को हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार शाम को विधायक डॉ. विकास चौधरी कांग्रेस पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ सड़क पर उतरे और स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। विधायक डॉ. चौधरी ने कहा कि मोबाइल पर आईजी राजेन्द्र सिंह से बात कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया और शिकायत की। विधायक डा चौधरी ने मोबाइल पर नगर परिषद के अधिकारी से भी बात कर अतिक्रमण हटाने के नाम पर जब्त किए सामान को तुरंत बिना किसी जुर्माना के व्यापारियों व ढेले वालो को लौटाने का निर्देश दिया। विधायक चौधरी ने कहा कि आखातीज गांव के किसानों के लिए होली दीवाली जैसा होता है। सावों की धूम रहती है। ऐसे में व्यापारियों व ठेले वालो को परेशान करना अतिक्रमण हटाना नहीं है। विधायक डा चौधरी अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मुख्य बाजार में पैदल मार्च किया और व्यापारियों व ठेले वालो से मुलाकात कर उन्हें संबल प्रदान किया। विधायक डा चौधरी ने पैदल मार्च के दौरान व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन ने बिना किसी नोटिस या सूचना के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर तोड़फोड़ की और व्यापारियों के सामान को जप्त किया, वह पूरी तरह से अनुचित और तानाशाही पूर्ण रवैया है।

लव जिहाद के बाद अब जिहाद का नया स्वरूप

प्राची शर्मा

महाराष्ट्र के नासिक और अमरावती में सामने आए हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और यौन शोषण से जुड़े मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इन घटनाओं ने न केवल कार्यस्थलों की सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह बहस भी तेज कर दी है कि क्या संगठित तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है ? अमरावती में सैंकड़ों लड़कियों के यौन शोषण को लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है तो वहीं नासिक में टीसीएस के ऑफिस में हुए धर्मांतरण और यौन शोषण मामले को कॉर्पोरेट जिहाद की संज्ञा दी जा रही है। पिछले साल पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर मारा था और अब देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आ रही घटनाएं दर्शा रही हैं कि धर्म के आधार पर निशाना बनाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सबसे आसान शिकार महिलाएं और लड़कियां बन रही हैं। सबसे पहले नासिक से सामने आये घटनाक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि एक प्रमुख आईटी कंपनी टीसीएस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। कई महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कई प्राथमिकी दर्ज की हैं और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

देखा जाये तो इस मामले ने बीपीओ और केपीओ क्षेत्र के कार्य वातावरण पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि रात की शिफ्ट, कमजोर निगरानी और पद पर बैठे लोगों की शक्ति का दुरुपयोग ऐसे मामलों को बढ़ावा देता है। कुछ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार व्यक्तिगत टिप्पणियों, अनुचित प्रस्तावों और दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में कथित तौर पर निजी तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की भी बात सामने आई है। एक पुरुष कर्मचारी ने भी मानसिक दबाव और जबरदस्ती धार्मिक आचरण अपनाने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि कार्यस्थल की सुरक्षा, शिकायत निवारण प्रणाली और निगरानी तंत्र को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक पर कई युवतियों को बहला फुसलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें फैलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवतियों से दोस्ती करता था, उनका विश्वास जीतता था और फिर उन्हें निजी संबंधों में फंसाकर वीडियो रिकॉर्ड करता था। बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल कथित तौर पर दबाव और ब्लैकमेल के लिए किया गया। आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

उधर, पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों से संपर्क करता था और धीरे-धीरे उन्हें अपने प्रभाव में लेता था। उसका सोशल मीडिया पर सक्रिय होना और दिखावटी जीवनशैली भी इस प्रक्रिया में सहायक रही। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस मामले में कोई संगठित नेटवर्क शामिल है या यह व्यक्तिगत स्तर का अपराध है।

इस बीच, दोनों मामलों ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। कुछ नेताओं ने इन घटनाओं को कार्यस्थल सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विफलता बताया है, जबकि अन्य ने इसे व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में उठाया है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर धर्मांतरण कराने वालों पर ठरअ-वअढअ लगाने की मांग की है।

बहरहाल, नासिक और अमरावती के ये दोनों मामले इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कार्यस्थलों और समाज में महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल अपराधों की रोकथाम और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

राज्य में खुलेंगी 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरियां - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर भवानी निकेतन में राज्यस्तरीय समारोह हुआ। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में 200 ई-लाईब्रेरी खोलने के साथ ही मूंडला में अंबेडकर पीठ में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। उनके आदर्शों के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र और सभी वर्गों को सशक्त एवं सक्षम करने का काम डबल इंजन सरकार कर रही है। युवा उनके सिद्धान्तों को आत्मसात कर राष्ट्र विकास में भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार में अब 28 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है।

योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा को एससी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 292 करोड़ से 3.75 लाख, एसटी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 534 करोड़ से 3.21 लाख , ओबीसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.62 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में ढाई हजार से अधिक लाभार्थियों को लोन दिया है। उन्होंने अंबेडकर के जीवन यात्रा पर आधारित दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आज पिछड़े वर्ग के उत्थान और सर्वांगीण विकास का आधार बन रही है।

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। पहले चुनाव में टिकट नहीं दिया। फिर हराने की कोशिश की। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। गांधी परिवार खुद को ही भारत रत्न देने में इतना व्यस्त रहा कि वे उन्हें भूल ही गए। उन्होंने नेहरू-इंदिरा को तो भारतरत्न दिया जो दल दशकों तक देश पर शासन करता रहा, उसी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के पुरोधा अंबेडकर के साथ ही सबसे बड़ा अन्याय किया। उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण ही उन्हें मंत्रिमंडल से मजबूरन इस्तीफा दिया। उनके बनाए संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया। सीएम ने इस मौके पर पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को डीबीटी से 1,363 करोड़ राशि हस्तांतरित की। 10 छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 भवनों का शिलान्यास किया।

DNA-293050